05 मई आजीविका दिवस

अंधियारे से उजाले की ओर ग्रामीण महिलाओं के बढ़ते कदम

समीर रंजन

कल तक घर के अंदर रहने वाली व किसी से बात करने में संकोच करने वाली ग्रामीण महिलाएं आज गांव-समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. समूह की बैठकों में बचत के साथ-साथ स्वरोजगार पर विशेष जोर दिया जाता है, ताकि खुद व परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. इसी सिलसिले में समूह की बैठक में जाने का मौका मिला. पलामू जिला अंतर्गत सतबरवा प्रखंड से करीब छह किलोमीटर दूर रब्दा गांव का एक टोला है फुलवरिया. इस गांव में जाने के लिए सड़क नाममात्र की है. उबड़-खाबड़ कच्ची सड़क से होते हुए हम पहुंचते हैं रब्दा गांव. गांव पहुंचते ही जानकारी मिलती है कि फुलवरिया टोला के एक घर में एसएचजी महिला समूह की बैठक चल रही है. दुर्गा स्वयं सहायता समूह की इस बैठक में हम भी शामिल होते हैं. हमें देखते ही एसएचजी महिलाएं उठकर स्वागत गान करती हैं और हमारा परिचय पूछती हैं और फिर शुरू होती है एसएचजी समूह के क्रियाकलापों पर चर्चा.

समूह की अध्यक्ष मुन्नी देवी और सचिव संगीता देवी कहती हैं कि छह जुलाई 2014 को दुर्गा समूह का गठन हुआ. कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखने वाली महिलाएं आज बेधड़क समूह के क्रियाकलापों की जानकारी दे रही हैं. समूह से जुड़ने से पहले की स्थिति और अब की स्थिति को भी बखूबी बताते नहीं थक रही थीं समूह की महिलाएं. गोद में बच्चा लिए एक एसएचजी सदस्य कहती हैं कि पहले घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी. समझ में नहीं आता था कि क्या करें, लेकिन जब से समूह से जुड़ी, बचत करने के तरीके समेत अन्य चीजों में भी परिवर्तन हुआ और इन सबका श्रेय आजीविका को जाता है. दुर्गा समूह में 11 सदस्य हैं और हर गुरूवार को समूह की बैठकें होती हैं. बैठक में पिछले सप्ताह का क्रियाकलाप और लेनदेन पर चर्चा होती है, वहीं आगामी दिनों की रूपरेखा भी तय की जाती है.

बैठक में प्रस्ताव पुस्तिका, उपस्थिति सह बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, सदस्यों के पास बुक, नगद पुस्तिका, साधारण खाता-बही पुस्तिका की विस्तृत जानकारी देती हैं. महिला समूहों की सदस्यों की बात सुन ऐसा लगता है मानो हम किसी गांव की नहीं बल्कि शहर की किसी महिला से बात कर रहे हैं.

यह तो मात्र एक बानगी है. ऐसे ही राज्य के सभी जिलों के 215 प्रखंडों के 15 लाख 35 हजार गरीब परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा गया है. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सखी मंडलों का संचालन होता है. ग्रामीण विकास विभाग के जरिये झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के तहत गठित सखी मंडल अब सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभुकों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. एक सखी मंडल में 10 से 15 गरीब ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा जाता है. आजीविका मिशन की ओर से उन्हें चक्रीय निधि दी जाती है एवं माइक्रो क्रेडिट प्लान बनता है, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता के साथ बैंक ऋण दिलाने में मदद दिलायी जा सके. सखी मंडल की महिलाएं टैबलेट दीदी, पशु सखी, कृषक मित्र, इंटरनल सीआरपी आदि के रूप में कार्यक्रम को गांवों में पूरी तरह से आगे बढ़ा रही हैं. इनका आत्मविश्वास नयी ऊंचाइंयों को छू रहा है. सखी मंडल के जरिये एक ओर जहां ग्रामीण महिलाएं बचत कर रही हैं, वहीं अपने संगठन से छोटे से बड़े ऋण के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान कर रही हैं. सखी मंडल, ग्राम संगठन (वीओ) एवं कलस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) जैसे संगठन के सहारे ग्रामीण महिलाएं बदलाव की वाहक बन रही हैं. सुदूर गांवों में बैंकिंग सुविधा पहुंचानी हो या शौचालय निर्माण में भागीदारी. अब सभी कार्यों में समूह की महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है.

कौशल विकास से के जरिए स्वावलंबी बनती युवतियां.

जोहार योजना

गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने राज्य में जोहार योजना की शुरुआत की है. इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आजीविका के साधनों से जोड़ कर उनकी आय में गुणात्मक वृद्धि करना है. इसमें 50 फीसदी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति को भी प्राथमिकता दी जा रही है. इसके तहत उन्नत खेती, पशुपालन, मछली पालन एवं लघु वनोपज पर सघन रूप से काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि ग्रामीण परिवारों को बड़े स्तर के उत्पादन के लायक बना कर उनकी आय में वृद्धि की जा सके. लाह, इमली, चिरौंजी, तुलसी, लेमन ग्रास, मुनगा एवं शहद जैसे अच्छी मांगवाले उत्पादों के जरिये आमदनी का नया रास्ता निकाला गया है. इसके तहत सिंचाई के आधुनिकतम साधनों की सुविधा भी सरकार उपलब्ध करायेगी. सखी मंडल की सदस्य आज सरकार की इसी नीति की बदौलत अपने गांव में उद्यमों से जुड़ कर अच्छी आमदनी कर रही हैं.

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी)

यह परियोजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है. इसका उद्देश्य छोटी जोतों के किसानों की स्थायी पद्धतियों में दक्षता बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि-परिस्थितिकी अपनाना, उन्नत पशु पालन पद्धतियों द्वारा पशु सखी को बढ़ावा देना आदि मुख्य है. जेएसएलपीएस द्वारा समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से राज्य में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है. इसके तहत भूमिहीन, छोटे व सीमांत किसानों पर अधिक ध्यान दिया जाना है. घरेलू व सामुदायिक स्तर पर खाद्य व पोषक सुरक्षा को प्रोत्साहित करना है. एमकेएसपी के कार्यक्षेत्र में वैल्यू चैन आधारित आजीविका, स्थायी कृषि, महिला किसान पाठशाला के जरिये किसानों का क्षमतावर्द्धन करना, लघु वनोपज उत्पाद पर जोर देना है.

सामुदायिक सेवा केंद्र

जेएसएलपीएस ने सखी मंडल के जरिये पंचायत स्तर पर सामुदायिक सेवा केंद्र की शुरुआत की है. इसके तहत सखी मंडल के सदस्यों को पावर टीलर, मिनी राइस मिल, पावर स्प्रेयर, रोटरी टीलर जैसे दर्जनों उपयोगी कृषि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं. कृषि विभाग की ओर से एक पंचायत क्षेत्र को उपकरणों के लिए दो लाख रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं, वहीं 25 हजार रुपये सखी मंडल अपना लगा रही है. सामुदायिक सेवा केंद्र के जरिये सखी मंडल गांवों में जरूरतमंदों को सस्ती दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध करा रही है.

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

आर्थिक व सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने के उद्देश्य से डीडीयू-जीकेवाई की शुरुआत हुई. इसके तहत ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रदान करते हुए उनके नियोजन में सहायता प्रदान करना है. गरीब ग्रामीण युवाओं को आर्थिक दृष्टि से उत्पादक तथा वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बनाना है. इस योजना के तहत ऑन द जॉब प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तक, अध्ययन सामग्री व ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शनयुक्त पीसी उपलब्ध कराना, आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में निःशुल्क भोजन व रहने की व्यवस्था करना है. प्रशिक्षण के उपरांत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाता है.

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

अब दूर-दराज के गांवों को मुख्य गांवों से जोड़ने तथा बाजार, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं ग्रामीणों को हर हाल में उपलब्ध हो, इसके लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत हुई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आजीविका प्रदान कराना है. इसके तहत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना है. इसमें ई-रिक्शा समेत तीन व चार पहिया वाहनों की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि दूर-दराज के गांवों को बाजार, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मुख्य सेवाओं व सुविधाओं से जोड़ा जा सके. ग्रामीणों को ई-रिक्शा समेत तीन-चार पहिया वाहनों की खरीद के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. सामुदायिक आधार संगठन यानी सीबीओ द्वारा अपने कोष से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वाहन खरीदने के लिए 6.50 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण दिया जायेगा. यह दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाइ-एनआरएलएम) के हिस्से के रूप में उप-योजना है. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आठ राज्यों- आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इस योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गयी है. राज्य प्रखंडों का चयन उन ब्लॉकों में से करेंगे, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सक्रिय रूप से कार्यरत है और जहां परिपक्व समुदाय आधारित संगठन पहले से काम कर रहे हैं. ब्लॉकों तथा मार्गों के चयन में पिछड़ापन, परिवहन संपर्क का अभाव और सतत सेवा की संभावना जैसी बातों का विशेष ध्यान रखा जायेगा.